Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 12-03-2007

Participants : Bhagora Shri Mahaveer

Title: Need for speedy implementation of pending power-projects in Rajasthan under 'Rajiv Gandhi Gramin Vidhutikaran Yojana'.

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : महोदय, भारत सरकार ने फरवरी, 2005 में विश्वसनीय एवं उचित गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति दक्षतापूर्ण तरीके से तर्कसंगत दरों पर करने, सभी घरों को अगले पांच वर्ों में विद्युत उपलब्ध करवाने और वर्ा 2012 तक विद्युत मांग की पूर्ण पूर्ति के मुख्य उद्देश्य से राट्रीय नीति घोाति की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिर्फ 44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में ही विद्युत उपलब्ध हो पाई है और अभी तक एक लाख से अधिक गांवों को विद्युतीकृत करना बाकी है।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रारंभ करने की घोाणा की जिसमें सभी अ वद्युतीकरण ग्रामों व ढाणियों को आगामी पांच वर्ों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार भी सम्मिलित हैं, के विद्युतीकरण सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है। गरीबी रेखा से नीचे जी वनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क कनैक्शन जारी करना सम्मिलित है। इस योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत का अनुदान तथा 10 प्रतिशत का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किया जाना है।

राजस्थान राज्य के 32 जिलों की 41 योजनाएं बनाकर निगम को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इन योजनाओं में 17,55,435 बी. पी.एल परिवारों व 52,790 सामान्य परिवारों को घरेलू कनैक्शन 4489 अविद्युतीकृत ग्रामों व 6600 ढाणियों को विद्युतीकृत करना है जिस पर 1091.49 करोड़ व्यय की लागत आंकी गई है।

निगम द्वारा 27 योजनाएं स्वीकृत की गई है जिनमें भीलवाड़ा व झालावाड़ जिलों की क्रियान्वित पी.जी.सी.आई.एल द्वारा प्रस्तावित है तथा शेा 25 योजनाएं संबंधित निगमों द्वारा टर्नकी आधार पर किया जाना है। 12 योजनाओं के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति इस बंदिश के साथ प्रापत हुई है कि जब निगम अधिकृत स्वीकृति जारी नहीं करता तब तक क्रियान्वयन का कांट्रेक्ट नहीं दिया जा सकता।

इस तरह इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विाय पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रधान मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्ति कर राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य की लंबित योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र दिलायी जाये।